सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 22 AUGUST TO 28 AUGUST 2025 • VOLUME 05 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

प्रेरणा

"कठिनाइयों के हर
रास्तों से गुजरना
क्या पता किस मोड़ पर
कामयाबी मिल जाए।"

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	33°	26°
शनिवार	30°	24°
रविवार	32°	26°
सोमवार	33°	26°
मंगलवार	29°	26°
बुधवार	31°	26°
वीरवार	30°	26°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost
E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्यसभा में भी पास, कानून तोड़ने पर 3 साल जेल

नई दिल्ली. राज्यसभा ने गुरुवार को विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच 'ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक' पारित कर दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा द्वारा पारित 'ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक' को राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया था। विधेयक के पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विधेयक के तीन पहलू हैं - "ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग", जिनमें से दो-तिहाई खंड (ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग) को बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

राज्यसभा में बोलते हुए वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक महत्वपूर्ण विषय है जो डिजिटल दुनिया में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसके तीन खंड हैं - पहला खंड ई-स्पोर्ट्स है, जिसमें लोग टीम बनाकर खेलते हैं, समन्वय सीखते हैं, रणनीतिक सोच रखते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने कई पदक भी जीते हैं। इस विधेयक में ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए एक प्राधिकरण बनाया जाएगा और इसे कानूनी मान्यता मिलेगी। दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम्स जिसमें सॉलिटेयर, शतरंज, सोडुकू आदि शामिल हैं। इस विधेयक में ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा और एक प्राधिकरण बनाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तीसरा खंड - 'ऑनलाइन मनी गेम' अब सार्वजनिक

स्वास्थ्य जोखिम बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया में दो-तिहाई वर्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा वर्ग है, तीसरा - ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण समाज में, खासकर मध्यम वर्ग के युवाओं में, एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसकी लत लग जाती है और परिवार की जमा-पूंजी खर्च हो जाती है। अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और इसमें 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर घोषित किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग एक जन स्वास्थ्य जोखिम बन गया है। इससे मनोवैज्ञानिक विकार, बाध्यकारी व्यवहार, हिंसक व्यवहार जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके कारण कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है।

अपराध और दंड

1. ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश या सुविधा प्रदान करना: 3 वर्ष तक का कारावास और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
2. मनी गेम्स का विज्ञापन: 2 वर्ष तक का कारावास और/या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना।
3. मनी गेम्स से संबंधित वित्तीय लेनदेन: 3 वर्ष तक का कारावास और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
4. बार-बार अपराध करने पर बढ़ी हुई सज़ा का प्रावधान है, जिसमें 3-5 वर्ष का कारावास और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है।
5. प्रमुख धाराओं के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

जाँच और प्रवर्तन की शक्तियां

1. केंद्र सरकार अधिकारियों को अपराधों से जुड़ी डिजिटल या भौतिक संपत्ति की जाँच, तलाशी और ज़ब्ती करने के लिए अधिकृत कर सकती है।
2. संदिग्ध अपराधों के कुछ मामलों में बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी और गिरफ्तारी करने के लिए अधिकारियों को अधिकार दिया गया है।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधान अधिनियम के तहत जाँच पर लागू होंगे।

केंद्र करे 50 हज़ार करोड़ के नुकसान की भरपाई : चीमा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/नई दिल्ली

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से ज़ोरदार मांग की है कि वह केंद्र की तरफ पंजाब के जीएसटी कारण हुये 50 हज़ार करोड़ रुपये के वित्तीय नुकसान की तुरंत भरपाई करे। स्वास्थ्य व बीमा, दरों को तार्किक बनाने और मुआवज़ा सेस से जुड़े मुद्दों पर हुई जीएसटी मंत्री समूह की दो दिवसीय बैठकों में हिस्सा लेने के बाद गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए स. चीमा ने कहा कि 2017 में देश में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने एक राष्ट्र-एक कर फार्मूले के तहत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया, जिसके चलते पंजाब को कुल 1,11,045 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि लगभग 60 हज़ार करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने मुआवज़े के तौर पर दिए, लेकिन अब भी 50 हज़ार करोड़ रुपये केंद्र के पास बकाया पड़े हैं।

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए पाँच साल तक मुआवज़ा देने का ऐलान किया था। उन्होंनें कहा कि केंद्र ने अब यह मुआवज़ा देना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जी.एस.टी. दरों को तार्किक बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि राज्यों को होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई की व्यवस्था ज़रूर की जाए।

चीमा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लगातार राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को तबाह कर रही है, जो देश के संघीय ढाँचे पर बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र पंजाब के फंड भी जारी करने से बच रहा है। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. से इतर भी ग्रामीण विकास फंड के 8,000 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री सड़क योजना के लगभग 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. लागू करते समय सभी राज्यों ने सहमति देकर केंद्र का साथ दिया था, लेकिन आज जब राज्यों के वित्तीय नुकसान की भरपाई का सवाल उठता है, तो केंद्र सरकार मुँह फेर लेती है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक जी.एस.टी. में 27 बार संशोधन किए गए हैं और 15 बार दरों में बदलाव हुआ है।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा

नई दिल्ली. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने संभाल ली है और अब उन्हें ज़ेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। यह कदम बुधवार सुबह सिविल लाइंस स्थित उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान उन पर हुए हमले के एक दिन बाद उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस से सीआरपीएफ को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है और अगले कुछ घंटों में इसके पूरा होने की उम्मीद है।

एक बार व्यवस्था तय हो जाने के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास की बाहरी सुरक्षा का प्रबंधन जारी रखेगी जबकि सीआरपीएफ सीधे तौर पर उनकी व्यक्तिगत और क्षेत्र-विशिष्ट सुरक्षा का प्रबंधन करेगी। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रेखा गुप्ता की चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। सीआरपीएफ वर्तमान में भारत में कई हाई-प्रोफाइल नेताओं को सुरक्षा प्रदान करती है जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गांधी परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, को ज़ेड या ज़ेड-प्लस सुरक्षा श्रेणी में रखा गया है। बुधवार सुबह सिविल लाइंस स्थित अपने कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पर हुए हमले के कुछ घंटों बाद उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने बाद में इस हमले को "उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश" करार दिया था। राजकोट (गुजरात) निवासी 41 वर्षीय आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री के हाथ, कंधे और सिर में चोटें आई हैं। जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ी पुलिस ने हमले के सिलसिले में हत्या के प्रयास के आरोप में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

साइबर फ्रॉड और हाईवे आपातकाल की रिपोर्ट के लिए 112 डायल करें

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

राज्य में आपातकालीन सेवाओं को अधिक सुलभ और कुशल बनाने के मद्देनज़र एक महत्वपूर्ण कदम के तहत पंजाब पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) हेल्पलाइन 1033 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 को एकीकृत कर अब डायल 112 से जोड़ दिया है। पंजाब की इस एकीकृत संकटकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से अब नागरिक हाईवे दुर्घटनाओं और अन्य वाहनों संबंधी समस्याओं के साथ-साथ वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराधों की रिपोर्ट सिर्फ 112 डायल कर सकते हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों के तहत लागू की गई यह पहल, एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के तहत कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती है और तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करती है।

उल्लेखनीय है कि पहले नागरिकों को धोखाधड़ी या सड़क हादसे की रिपोर्ट करने के लिए खास हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करनी पड़ती थी, जिससे उनके लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर याद रखना मुश्किल हो जाता था। अब तक 112 हेल्पलाइन का उपयोग केवल राज्यभर में होने वाले विभिन्न अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए ही किया जाता था।

अंतर-राज्यीय म्यूल अकाउंट रैकेट का पर्दाफाश; 10.96 लाख नकद सहित चार गिरफ्तार

नौ मोबाइल, एक लैपटॉप, 32 डेबिट कार्ड और 10 सिम कार्ड बरामद

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब पुलिस के स्टेट साइबर क्राइम विंग ने चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ देशभर में हजारों पीड़ितों से करोड़ों रुपये की ठगी में शामिल एक अंतर-राज्यीय म्यूल अकाउंट रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने गुरुवार को यहां दी। गौरतलब है कि म्यूल अकाउंट ऐसा बैंक खाता होता है, जिसे अपराधियों द्वारा खाता धारक की जानकारी के बिना या कई बार मिलीभगत से अवैध धन प्राप्त करने, ट्रांसफर करने या लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गौतम (23),

अहसास (24) और आकाश (20), तीनों अमृतसर निवासी, तथा अनमोल (21) निवासी फाजिल्का के रूप में हुई है। अनमोल पूरा समय म्यूल अकाउंट चलाने में शामिल था, गौतम बेरोज़गार है, अहसास अमृतसर में कांट्रैक्ट पर होटल चलाता है और आकाश पहले थोड़े समय तक एक कंपनी में काम कर चुका है तथा वर्तमान में म्यूल अकाउंट साइबर धोखाधड़ी रैकेट में शामिल था। पुलिस ने उनके कब्जे से 10.96 लाख रुपये नकद, नौ मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 32 डेबिट कार्ड, 10 सिम कार्ड, 15 बैंक पासबुक और एक चैक बुक बरामद की है।

डीजीपी ने कहा कि यह रैकेट बैंकों के खाते, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के खाते, थोड़ी राशि देने का लालच देकर हासिल कर लेता था और फिर उनका इस्तेमाल विभिन्न साइबर अपराधों से प्राप्त धोखाधड़ी वाले धन को लेयरिंग और ट्रांसफर करने के लिए करता था। स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम वी. नीरजा ने कहा कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आइ4सी), गृहमंत्रालय द्वारा साझा किए गए साइबर धोखाधड़ी बैंक ट्रांसफर में इस्तेमाल हुए 6,000 म्यूल अकाउंट के डेटा के गहन विश्लेषण के बाद डीएसपी अशोक कुमार द्वारा स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।

60,000 रुपये रिश्वत लेते क्लर्क को विजीलेंस ने रंगे हाथ पकड़ा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने ज़िला विकास और पंचायत कार्यालय (डीडीपीओ) फ़िरोज़पुर में तैनात क्लर्क बलवंत सिंह को 60,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। राज्य विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उक्त आरोपी को फ़िरोज़पुर ज़िले की तहसील तलवंडी भाई के गाँव लल्ले के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

शिकायत के अनुसार, उक्त क्लर्क ने शिकायतकर्ता को धमकाया कि यदि वह पंचायत ज़मीन का ब्यौरा बैंक में जमा कराएगा तो उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई से बचाने के लिए क्लर्क ने 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की। बाद में वह 60,000 रुपये रिश्वत लेने पर सहमत हो गया।

इस क्लर्क के खिलाफ़ विजीलेंस ब्यूरो थाना फ़िरोज़पुर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा और इस केस की आगे की जांच जारी है।

आईटी 2.0 : डाक सेवाओं के नए डिजिटल युग की शुरुआत

उन्नत डाक प्रौद्योगिकी, डिजिटल इंडिया की ओर भारतीय डाक की यात्रा में एक मील का पत्थर

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल विजन को गति देते हुए केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के मार्गदर्शन में डाक विभाग (डीओपी) ने आईटी 2.0 - उन्नत डाक प्रौद्योगिकी (एपीटी) को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह ऐतिहासिक डिजिटल उन्नयन विभाग के 1.65 लाख डाकघरों में आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया विज़न को सशक्त बनाते हुए देश के हर कोने में तेज, विश्वसनीय और नागरिक-केंद्रित डाक तथा वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराएगी, जो समावेशिता और सेवा उत्कृष्टता के प्रति भारतीय डाक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। पूर्व आईटी आधुनिकीकरण

परियोजना 1.0 की सफलता पर आधारित नया एपीटी प्लेटफ़ॉर्म माइक्रोसर्विसेज़-आधारित अनुप्रयोग पर कार्य करता है, जो नागरिकों को तीव्र, विश्वसनीय और उपयोगकर्ता-अनुकूल सेवाएँ प्रदान करता है। यह प्रणाली डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (सीईपीटी) द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित की गई है। एप्लिकेशन भारत सरकार के मेघराज 2.0 क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट है और बीएसएनएल की राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी द्वारा समर्थित है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि, "एपीटी भारतीय डाक को एक विश्वस्तरीय सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में परिवर्तित करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो एक मज़बूत और आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।" एपीटी की प्रमुख विशेषताओं में माइक्रो-सर्विसेज़ और ओपन एपीआई आधारित आर्किटेक्चर, एकीकृत उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, क्लाउड-रेडी परिनियोजन, बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक संपूर्ण डिजिटल समाधान, क्यूआर कोड भुगतान और ओटीपी-आधारित डिलीवरी जैसी अगली पीढ़ी की सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह ओपन नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, डिलीवरी की सटीकता बढ़ाने हेतु 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक DIGIPIN पेश करता है और बेहतर रिपोर्टिंग एवं विश्लेषण क्षमता प्रदान करता है।

इस परियोजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से किया गया। कर्नाटक डाक मंडल (मई-जून 2025) में सफल पायलट के बाद अधिगमों को शामिल करते हुए प्रणाली को और परिष्कृत किया गया। इसके बाद 22 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक पंजाब सर्कल में चरणबद्ध रोलआउट किया गया। अंततः 4 अगस्त 2025 को सभी 23 डाक सर्कलों में इसका सफल समापन हुआ, जिससे देशभर के 1.70 लाख से अधिक कार्यालय (डाकघर, मेल कार्यालय और प्रशासनिक इकाइयाँ) एपीटी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ गए। यह समझते हुए कि किसी भी तकनीकी परिवर्तन की सफलता उसके कार्यबल पर निर्भर करती है, भारतीय डाक ने "प्रशिक्षण - पुनःप्रशिक्षण - नवीनीकरण" के सिद्धांत के तहत मास्टर प्रशिक्षकों, उपयोगकर्ता चैंपियनों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को सम्मिलित करते हुए एक कैस्केड मॉडल के माध्यम से 4.6 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। इससे हर स्तर पर तत्परता सुनिश्चित हुई और देशभर में इसका सहज क्रियान्वयन संभव हुआ।

नई प्रणाली ने अपनी लचीलापन और मापनीयता साबित करते हुए एक ही दिन में 32 लाख से अधिक बुकिंग और 37 लाख डिलीवरी सफलतापूर्वक संपन्न की। आईटी 2.0 के पूरा होने के साथ भारतीय डाक ने एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित सेवा प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति को और सशक्त किया है तथा विश्वास और बेजोड़ पहुँच की अपनी विरासत को कायम रखा है। यह सफलता भारतीय डाक के कार्यबल के समर्पण का प्रमाण है और ग्रामीण-शहरी डिजिटल खाई को पाटने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा प्रत्येक नागरिक को विश्वस्तरीय सेवाएँ प्रदान करने की उसकी प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ करती है।

पीएम मोदी को राष्ट्रपति मैक्रों का कॉल आया

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वीरवार को फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बात हुई। नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

राष्ट्रपति मैक्रों ने वाशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठकों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने गाजा की स्थिति पर भी अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान तथा शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहित द्विपक्षीय सहयोग एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने और 2026 को 'नवाचार वर्ष' के रूप में मनाने की संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए भी समर्थन व्यक्त किया।

मानसून के बाद साउथ इंडिया के इन हिल्स की करें सैर, हरी-भरी वादियां हैं देखने लायक

Travelling

मानसून के बाद किसी सुंदर जगह की सैर करने के लिए प्लान बना रहे हैं तो साउथ इंडिया में बने इन प्राकृतिक नजारों से भरपूर इन 5 हिल स्टेशन की सैर कर लें। मानसून के बाद यहां पर नेचर और चारों तरफ हरियाली सुंदर...

• **जालंधर ब्रीज. फीचर**

मानसून के बाद नेचर के नजारे बेहद सुंदर दिखते हैं। खासतौर पर पहाड़ों और हिल स्टेशन पर चारों तरफ हरे-भरे पहाड़ और घास के मैदान नजर आते हैं। वहीं मौसम हल्का ठंडा हो जाता है। प्रकृति के ऐसे सुंदर नजारे देखने हैं तो साउथ इंडिया के इन 5 हिल स्टेशन पर जाएं। मन की सारी थकान दूर हो जाएगी।

मन्नार, केरल

केरल के इडुक्की जिले में बना मन्नार हिल स्टेशन अपने सुंदर नजारों की वजह से फेमस है। मानसून की बारिश के बाद यहां की हरियाली और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही नदियों में पानी भी ज्यादा रहता है। अगर आप इस हिल स्टेशन पर जा रहे तो यहां बने इराविकुलम नेशनल पार्क में भी एक बार जरूर जाएं। जहां पर काफी सारे दुर्लभ प्रजाति के जीव-जन्तु देखने को मिल सकते हैं। वहीं 12 सालों में एक बार खिलने वाला नलाकुरंजी फूल भी दिख सकता है। फ्रेश हवा और सुंदर नजारों को एक साथ देखना है तो इस हिल स्टेशन पर जरूर एक बार जाएं।

वागामोन

केरल के इडुक्की जिले में ही पीरूमेदु तुलुक में बसा है वागामोन हिल स्टेशन। इस हिल स्टेशन पर घास के मैदान, ऊंचे पाइन के पेड़ और मानसून के बाद बिखरी चारों तरफ हरियाली दिखती है। धुंध से घिरी घाटी को देखने के लिए वागामोन पर बना ब्रिज शानदार जगह है। मानसून के बाद पेड़ से लेकर घास तक में जान आ जाती है और ये ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। मानसून में ट्रेवल करने के लिए वागामोन हिल स्टेशन बेस्ट डेस्टिनेशन है।

अगुंबे

कर्नाटक में बसे इस हिल स्टेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कोस्टल एरिया और प्लेन कर्नाटक को जोड़ने वाले इस हिल स्टेशन पर मानसून में चारों तरफ हरियाली दिखती है। इस जगह पर इतनी बारिश होती है कि इसे साउथ का चेरापूंजी बोला जाता है। यहां पर कई सारे वाटरफाल्स हैं। बरकाना, जोगी गुंडी वाटरफाल्स और ओनाके अब्बी वाटरफाल्स। इस हिल स्टेशन पर कई सारे ट्रैक है। जहां कई सारे जीव-जन्तु जिसमे सांप, मेढ़क,कीड़े और कई सारे पेड़-पौधे शामिल है, देखने को मिलते हैं।

कोडाइकनाल

तमिलनाडु का ये हिल स्टेशन काफी फेमस है। इसे प्रिंसेज ऑफ हिल्स के नाम से लोग जाते हैं। जहां जंगल और पहाड़ पर चारों तरफ हरियाली फैली दिखती है। कोडाइकनाल अपनी स्टार शेप की मैन मेड झील के लिए भी फेमस है। बारिश के बाद किसी सुंदर जगह सुकून की तलाश में हैं तो 10-20 डिग्री के तापमान में यहां के सुंदर व्यू प्वाइंट को देखने जरूर जाएं।

पैथलमाला, केरल

केरल के कन्नूर जिले में ही बसा है सुंदर नजारों से भरपूर हिल स्टेशन पैथलमाला। जिसे पथईमाला भी कहते हैं। ये हिल स्टेशन ट्रैकिंग करने वालों के बढ़िया है। यहां से कुर्ग की वैली, एजाराकुंडु वाटर फाल जैसे नजारे ट्रैकिंग के दौरान देखने को मिलते हैं। रोज की भागदौड़ से दूर कहीं जाना चाहते हैं तो ये हिल स्टेशन बेस्ट जगह है।

FITNESS COACH

सेहत को गजब फायदा पहुंचाते हैं बीज, ज्यादा बेनिफिट्स के लिए चुनें खाने का सही तरीका

बीजों को सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। लेकिन अगर सही तरह से इन्हें न खाया जाए तो कुछ खास फायदा नहीं मिलता। इस आर्टिकल में जानिए ज्यादा बेनिफिट्स पाने के लिए कैसे खाएं बीज...

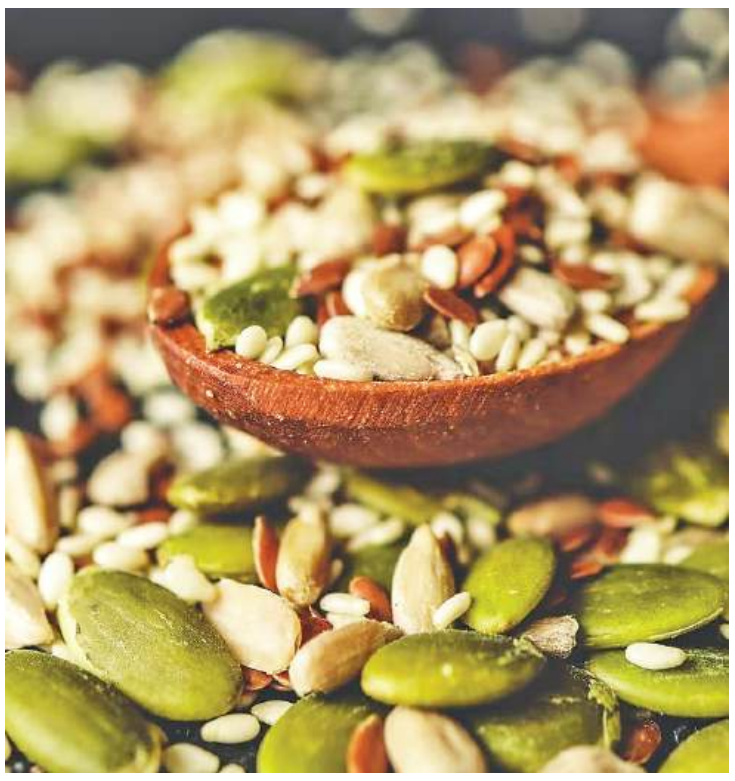

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

बीजों को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। ये सुपरफूड होते हैं। हेल्दी रहने के लिए रोजाना बीजों को खाना एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कुछ लोग कच्चे बीजों को खाना पसंद करते हैं या फिर भिगोकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन हर बीज को खाने का एक अलग तरीका होता है। डायटीशियन शिवानी कंडवाल ने ज्यादा फायदे पाने के लिए अलग-अलग बीजों को खाने का तरीका बताया है।

1) कद्दू के बीज- इन बीजों को आप कच्चा खा सकते हैं या फिर हल्का रोस्ट करके खाएं। जिंक और प्रोटीन से भरपूर इस बीज को लंच के बाद एक चम्मच खाएं।

2) अलीव या हलीम सीड्स- इसे पानी में भिगोएं। फिर पीस लें और घी या नारियल के तेल में मिलाकर खाएं। ये हार्मोन और बालों के लिए अच्छा होता है।

3) चिया सीड्स- फाइबर और ओमेगा 3 से भरपूर चिया सीड्स को 30 मिनट के लिए पानी में भिगोएं। फिर इसे स्मूदी या नींबू पानी में मिलाकर पिएं। वेट लॉस करने के लिए अधिकतर लोग इन बीजों को खाते हैं।

4) सब्जा सीड्स- 10 से 15 मिनट के लिए इन भीजों को भिगोएं। फिर इसे पानी में मिलाकर खाएं। ये ब्लोटिंग को शांत करने में मदद करता है।

5) तिल के बीज- ये बीज कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इन बीजों को खाने के लिए बीजों को रोस्ट करें और फिर पीस लें। अब गुड़ के साथ या चटनी के साथ मिलाकर इसे खाएं।

6) अलसी के बीज- अलसी के बीज एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं। हॉर्मोन बैलेंस करने वाले इन बीजों को आप दही, स्मूदी या फिर आटे में मिलाकर खा सकते हैं।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

घर में बनाएं नो ऑयल वाला तंदूरी आलू पराठा, बच्चे-बड़े सब चट कर जाएंगे

त्योहार के बाद वाले वीकेंड पर कुछ सरल सी चीज बनाने का मन है तो फटाफट से बिना तेल-घी लगाए बना लें ढाबा स्टाइल तंदूरी आलू का पराठा। साथ ही सीख लें पराठा मसाला में कौन-कौन से मसाले डाले जाते हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

त्योहार के बाद वाला वीकेंड काफी लेजी होता है। ऐसे में सारे काम लेट हो जाते हैं। वीकेंड पर ब्रेकफास्ट और लंच के झंझट से फ्री होना है तो फटाफट ब्रच रेडी कर लें। जिसे खाने के बाद बच्चे और घर के बड़े दोनों ही तारीफ करेंगे और जमकर खाएंगे। इस वीकेंड आप आलू के तंदूरी पराठे बनाकर तैयार करें। बिना पहले से तैयार किए ये पराठे आसानी से बन जाते हैं और खाने में टेस्टी होते हैं। तो चलिए जानें कैसे बनाएं तंदूरी आलू पराठा।

तंदूरी आलू पराठा की सामग्री

- गेंहू का आटा एक कप
- चीनी आधा चम्मच
- आधा चम्मच नमक
- एक चौथाई कप दही
- पानी जरूरत के अनुसार
- एक चम्मच देसी घी
- तीन चम्मच धनिया
- एक चम्मच सौंफ
- एक चम्मच अजवाइन
- एक चम्मच जीरा
- सूखी लाल मिर्च
- एक चम्मच काली मिर्च
- तीन से चार उबले आलू
- एक चम्मच अमचूर पाउडर
- गरम मसाला
- नमक
- हींग
- प्याज
- हरी मिर्च, हरी धनिया

तंदूरी आलू पराठा बनाने की रेसिपी

- तंदूरी आलू पराठा बनाने के लिए गेंहू के आटे को किसी बड़े थाली में लें।
- उसमे नमक और चीनी आधा चम्मच डालें। साथ ही एक चौथाई कप नॉर्मल टेंपरेचर में रखी दही डाल दें। ध्यान रहे कि ये बहुत ज्यादा खट्टी ना हो।
- पानी डालकर मुलायम आटा गूंथ लें और एक चम्मच घी डालकर फिर से अच्छी तरह से गूंथकर ढंक दें.
- आलू की फिलिंग के लिए आलू उबालकर ठंडा कर लें।
- अब पराठा मसाला बनाने के लिए किसी पैन में धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, लाल मिर्च को ड्राई रोस्ट कर लें।
- मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें।
- उबले आलू को मैश कर लें और पराठा मसाला के साथ ही हींग, हल्दी, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल कर आलूओं को मैश कर लें।
- तैयार आटे की लोई बनाकर आलू भरें और तवे पर सेंके।
- तवे पर सेंकते वक्त ध्यान रखें कि फ्लेम धीमी हो जिससे पराठे अंदर तक सिंक जाएं और फिर पराठे को गैस पर डायरेक्ट रखकर एक मिनट तक अलट-पलट कर सेंकते रहें।
- बस रेडी है मजेदार तंदूरी ढाबा स्टाइल आलू का पराठा। इसे चटनी, रायता के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

बच्चों को मोबाइल देने से पहले जरूर समझा दें ये बातें

Parenting

जालंधर ब्रीज (फीचर) . बदलते समय के साथ ना सिर्फ लोगों के रहन-सहन और खानपान में बदलाव आया है बल्कि बच्चों के पढ़ाई करने के तरीके भी पूरी तरह से बदल गए हैं। आज पढ़ाई से लेकर ऑनलाइन क्लास और एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स, हर काम के लिए स्मार्टफोन जरूरी हो गया है।

याद रखें, बच्चों को मोबाइल के साथ अगर सही गाइडेंस ना दी जाए तो इंटरनेट, सोशल मीडिया और गेम्स की लत उनकी पढ़ाई, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर बुरा असर डाल सकती है। इससे बचने के लिए आइए जान लेते हैं बच्चे को स्मार्टफोन देने से पहले पेरेंट्स को कौन सी 5 बातें बच्चों को जरूर समझानी चाहिए।

सीमित स्क्रीन टाइम - बच्चों को स्मार्ट फोन देते समय उनका स्क्रीन टाइम जरूर फिक्स कर दें। बच्चों को समझाएं कि ज्यादा देर मोबाइल देखने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। जिससे ना सिर्फ उनकी पढ़ाई बल्कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

डिवाइस केयर - बच्चों को स्मार्ट फोन देते समय डिवाइस केयर की जानकारी भी दें। उन्हें समझाएं कि कैसे पानी, धूल उनके फोन को खराब कर सकते हैं। मोबाइल का रख-रखाव उनके मोबाइल को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है।

ऑनलाइन सुरक्षा की जानकारी - बच्चों को मोबाइल देने से पहले यह जरूर समझाएं कि उन्हें फोन पर अनजान लोगों से चैट नहीं करनी है। इसके अलावा किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने के खतरे से भी उन्हें अवगत करवाएं। उन्हें समझाएं कि किसी भी अजनबी के साथ फोन पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करनी है।

सोशल मीडिया पर सतर्कता - बच्चों को समझाएं कि सोशल मीडिया पर क्या चीज शेयर करनी है और क्या नहीं। गलत पोस्ट, फोटो या वीडियो भविष्य में उनके लिए कैसे परेशानी की वजह बन सकती हैं।

रियल और सोशल लाइफ में बैलेंस - देखा जाता है कि बच्चे बाहर दोस्तों के साथ खेलने या पेरेंट्स के साथ बात करने की जगह फोन पर समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में बच्चों को फोन की जगह दोस्तों के साथ खेल, किताबों और परिवार के साथ समय बिताने का महत्व समझाएं।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

आखिर क्यों पेट की एक्सरसाइज करने के बाद भी बेली फैट कम नहीं होता?

Health

लगातार कई महीनों से क्रंच और दूसरी पेट की एक्सरसाइज करने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। दरअसल, इसके पीछे बॉडी का साइंस है। जिसमे मुताबिक केवल शरीर के एक हिस्से की एक्सरसाइज करने से वहां का...

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

मोटापा कई सारी बीमारियों को न्योता देता है। खासतौर पर बेली फैट, अगर पेट पर फैट ज्यादा है तो ये ना केवल ओबेसिटी के खतरे को बढ़ाता है बल्कि इससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने की वजह से हार्ट डिसीज का रिस्क रहता है। इसलिए बेली फैट को घटाना जरूरी होता है। लेकिन बढ़े पेट को कम करने के लिए अगर आप केवल क्रंचेज और दूसरी केवल पेट से जुड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो इससे बेली फैट कम नहीं होता। जिसकी वजह से काफी सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। दरअसल, शरीर के किसी खास हिस्से का वजन घटाने के लिए केवल उस स्पेसिफिक जगह की एक्सरसाइज करने से फर्क कम पड़ता है। जानें क्या कहते हैं डॉक्टर।

इन वजहों से कम नहीं होता बेली फैट

दरअसल, जब केवल क्रंचेज और बेली फैट की एक्सरसाइज करते हैं तो इससे विजिबल इफेक्ट नहीं दिखता। ये हैं इसके कारण...

फैट लॉस सिस्टमेटिक होता है

जब तक आप फुल बॉडी वर्कआउट नहीं करते तब तक विजिबल इफेक्ट नहीं दिखता। क्योंकि पेटी की एक्सरसाइज करने और कैलोरी कम खाने की वजह से शरीर एनर्जी के लिए इडिबल फैट सेल्स को तोड़ता है। लेकिन ये फैट सेल्स पेट के होंगे ये जरूरी नहीं। बॉडी सिस्टमेटिक तरीके से शरीर के हर हिस्से से फैट सेल्स को तोड़ती है। जिसकी वजह से फुल बॉडी वर्कआउट बेली एक्सरसाइज की तुलना में ज्यादा तेजी से असर करता है। इसलिए केवल पेट की एक्सरसाइज करने से बेली फैट घटने का असर बहुत कम दिखता है।

तेजी से बेली फैट घटाने के लिए क्या करें

तेजी से बेली फैट घटाना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस बेस्ड एक्सरसाइज करें। जिससे मेटाबॉलिक रेट बढ़े साथ ही मसल टोन होकर इम्प्रूव हो। इसके साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पूरी बॉडी ज्यादा स्लिम और स्कल्पटेड दिखती है।

इसके साथ ही न्यूट्रिशन का भी पूरा ध्यान रखें। प्रोटीन, फाइबर के साथ जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डाइट में खाएं। ये बॉडी को जरूरी एनर्जी देने में मदद करेंगे

इसके साथ ही पूरी नींद जरूरी है और स्ट्रेस को खुद से दूर रखें। नींद पूरी होने से मसल्स के रिकवरी में ज्यादा मदद मिलती है। इसलिए शरीर के एक हिस्से का भी वजन घटाना है तो पूरे बॉडी का वर्कआउट जरूरी है।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

गृह मंत्री ने आपदा से बचाव के बारे में ज़िला और ग्राम पंचायत स्तर तक जागरूकता फैलाने की जरूरत पर बल दिया

• **जालंधर ब्रीज .** नई दिल्ली

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 'आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण' पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार, समिति के सदस्य और केंद्रीय गृह सचिव के साथ-साथ गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), महानिदेशक (अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले आपदा प्रबंधन के प्रति राहत-केंद्रित अप्रोच थी, जिसे मोदी सरकार ने अप्रोच और स्ट्रेटेजी में बदलाव करते हुए बचाव केन्द्रित बनाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई बड़े नीतिगत और संस्थागत फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की डिजास्टर रिस्पॉन्स की नीति क्षमताओं का निर्माण, तीव्रता, दक्षता और सटीकता के चार पिलर्स पर आधारित है। इसके परिणामस्वरूप आपदाओं से काफी बचाव हुआ है, जहां 1999 में ओडिशा में आए महाचक्रवात में 10,000 लोगों की जान गई थी, जबकि गुजरात में 2023 के बिपरजॉय और 2024 में ओडिशा के दाना में हताहतों की शून्य रही। गृह मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मोदी सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप चक्रवातों के कारण होने वाले नुकसान में 98 प्रतिशत और heat wave के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। गृह मंत्री ने कई राज्यों में हाल की बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि बादल फटने की घटनाओं और भूस्खलन से निपटने के लिए रणनीति बनाई जा रही है।

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वित्तीय, संस्थागत और संरचनात्मक सशक्तिकरण के साथ ही मल्टी-डायमेंशनल अप्रोच को अपनाया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का फोकस आपदाओं से होने वाले नुकसान से लोगों को सुरक्षित रखने का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 10-सूत्रीय एजेंडा के आधार पर 2024 में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक लाया गया था जिसे transparency, responsibility, efficiency और synergy के साथ बांधने का काम किया गया है। गृह मंत्री ने आपदा से बचाव के बारे में ज़िला और ग्राम पंचायत स्तर तक जागरूकता

फैलाने की ज़रूरत पर बल दिया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2004-2014 में SDRF और NDRF को 66 हज़ार करोड़ रूपए दिए गए थे, 2014-2024 के 10 वर्ष में इसे लगभग तीन गुना बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रूपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए SDRF के लिए 1,28,122 करोड़ रुपये और NDRF के लिए 54,770 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) के लिए 13,693 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) के लिए 32,031 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं।

अमित शाह ने बताया कि आपदा से प्रभावित राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (IMCT) भेजने की औसत 96 दिन से घटकर 8 दिन रह गई है और पिछले 10 वर्षों में 8 दिन की औसत के साथ राज्यों में 83 केन्द्रीय दल भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि NDMA ने तकनीक के उपयोग और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण काम किया है, जबकि NDRF ने इसे बखूबी ज़मीन पर उतारा है। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP) के अंतर्गत बहुद्देशीय चक्रवात आश्रयों का निर्माण किया गया और 92,995 सामुदायिक स्वयंसेवकों एवं सरकारी अधिकारियों को चक्रवात न्यूनीकरण का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, 5 तटीय राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ भी स्थापित की गईं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित बुनियादी ढाँचा विभिन्न चक्रवातों के दौरान जान बचाने में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है।

अमित शाह ने कहा कि आपदा मित्र योजना और युवा आपदा मित्र योजना के कार्यान्वयन के साथ, सरकार सामुदायिक स्तर पर क्षमता के विकास और आपदाओं के दौरान सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है। आपदा मित्र योजना के अंतर्गत, विभिन्न आपदाओं के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिये 350 आपदा संभावित जिलों में एक लाख सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। सरकार ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपये की एक योजना भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत राज्यों को नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी बताया कि पहली बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शमन कोष का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) के लिए 13,693 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) के लिए 32,031 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। NDMF के अंतर्गत 8072 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ अनेक शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पूर्व चेतावनी के प्रसार में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और केंद्रीय जल आयोग (CWC) अब बाढ़ और चक्रवातों का 7 दिन पहले सटीक पूर्वानुमान देते हैं। लोगों तक अलर्ट पहुँचाने के लिये अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिये केंद्र सरकार ने SMS, तटीय सायरन आदि के माध्यम से पूरे देश में एकीकृत अलर्ट प्रणाली (CAP) पर आधारित एक 'कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल' लागू किया है। गृह मंत्री ने आपदाओं की अग्रिम चेतावनी देने वाली 'सचेत ऐप' का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार पर बल दिया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने बैठक में 'आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण' जैसे महत्वपूर्ण विषय को उठाने और बहुमूल्य सुझाव देने के लिए समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया। समिति के सदस्यों ने भी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की सराहना की। गृह मंत्री ने कहा कि आपदाओं की सूचना से सम्बंधित ऐप, गाइडलाइन और 10 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी आपदा फण्ड की जानकारी सभी सांसदों को भेजे जायेंगे।

नशा एक धीमा जहर, जो परिवारों और समाज को तोड़ रहा : राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया

• **जालंधर ब्रीज .** चंडीगढ़

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने 15-16 अगस्त 2025 को चंडीगढ़ और पड़ोसी राज्यों में "#नशे से आज़ादी" थीम के तहत एक बहुआयामी जागरूकता अभियान का आयोजन किया। यह अभियान छात्रों, आम जनता, दवा क्षेत्र और लाखों नागरिकों तक जमीनी गतिविधियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुँचा और नशा मुक्त भारत का संदेश फैलाया।

यह अभियान AKSIPS-41 स्मार्ट स्कूल से शुरू हुआ, जहाँ NCB चंडीगढ़ के अतिरिक्त निदेशक, IRS, अमनजीत सिंह ने छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कानूनी परिणामों और इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर संबोधित किया। छात्रों ने "नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें" का संकल्प लिया। बाद में शाम को, नेक्सस एलांते मॉल में एक जीवंत आउटरीच कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, छात्र नृत्य प्रदर्शन, अमनदीप सिंह (स्टील मैन ऑफ इंडिया) द्वारा एक प्रेरक व्याख्यान और एक प्रसिद्ध पंजाबी गायक के गीतों ने नशा-विरोधी संदेश को रचनात्मक रूप से पुष्ट किया और नागरिकों पर गहरा प्रभाव डाला। एनडीपीएस (आरसीएस) आदेश, 2013 के तहत समान पंजीकरण संख्या (यूआरएन) धारकों के लिए एक संवेदीकरण कार्यशाला भी आयोजित की गई। 20 दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने नियंत्रित पदार्थों के अनुपालन, रिकॉर्ड रखने और जिम्मेदारी से संचालन पर विचार-विमर्श किया, जो जिम्मेदार प्रथाओं के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

व्यापक पहुँच के लिए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के माध्यम से रेडियो प्रसारण और एसएमएस अलर्ट के माध्यम से नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए, जो लाखों ग्राहकों तक सीधे पहुँचे। एक सशक्त सोशल मीडिया अभियान ने इस संदेश को और व्यापक बनाया, जिसमें गुलाब चंद कटारिया (पंजाब के राज्यपाल), सागर प्रीत हुड्डा (डीजीपी चंडीगढ़), ओ.पी. सिंह (हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक), आईजी एएनटीएफ चंडीगढ़, जयराज सिंह धालीवाल और अभिनेत्री आलिया भट्ट सहित प्रमुख हस्तियों की सक्रिय भागीदारी रही, जिनकी अपीलों ने अभियान को व्यापक दृश्यता और पहुँच प्रदान की।

पंजाब के माननीय राज्यपाल, गुलाब चंद कटारिया ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नशा एक धीमा ज़हर है जो परिवारों और समाज को तोड़ता है। उन्होंने इस बुराई को खत्म करने में राज्य पुलिस, एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो एजेंसियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयासों की सराहना की। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने नशे को जीवन और समाज के लिए एक गंभीर खतरा बताया और सभी से "नशे को ना और जीवन को हाँ" कहने का आग्रह किया और नागरिकों को ई-शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हूडा ने लोगों से जीवन बचाने और इस सामाजिक अभियान को समर्थन देने के लिए 1933 'मानस' राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन पर कॉल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस का मिशन नशीली दवाओं के व्यापार को जड़ से समाप्त करना है। चंडीगढ़ स्थित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के महानिरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने समाज से नशा मुक्त समुदाय के निर्माण में पूर्ण सहयोग देने की अपील की। प्रवर्तन, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी की त्रि-आयामी रणनीति के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हुए, एनसीबी चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने आश्वस्त किया कि सामूहिक प्रयासों, निरंतर जन-संवेदनशीलता तथा सक्रिय नागरिक भागीदारी के माध्यम से वह एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा-मुक्त भारत के निर्माण के मिशन को आगे बढ़ाता रहेगा।

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

जालंधर ब्रीज (नई दिल्ली) . भारत के आदिवासी समुदाय, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% हैं, राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी, इन समुदायों के कई व्यक्ति जानकारी के अभाव में सिकल सेल नामक अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे हैं। दशकों से इस बीमारी ने उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर डाला है, और यह बीमारी भौगोलिक अलगाव एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच के कारण और भी जटिल हो गई है। इस गंभीर आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में जुलाई 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। इस मौलिक पहल का उद्देश्य न केवल सिकल सेल के आनुवांशिक संचरण का उन्मूलन करना है, बल्कि इस रोग से प्रभावित लाखों लोगों के सम्मान और स्वास्थ्य को भी बहाल करना है।

जगत प्रकाश नड्डा
(केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री)

सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, जिससे उनकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और धीरे-धीरे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न होने लगती हैं। आदिवासी जनसंख्या के बीच इसका प्रभाव विशेष रूप से गहरा है, क्योंकि वे इस आनुवंशिक बीमारी से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एस्टिमेट्स (2021) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति वर्ष अनुमानित 82,500 बच्चों का जन्म सिकल सेल रोग के साथ होता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने इस संकट से निपटने के लिए आधार तैयार किया और इसकी विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ज़ोर इसी के आधार पर, केंद्रीय बजट 2023 में NSCAEM की घोषणा की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-2026 तक 40 वर्ष से कम आयु के 7 करोड़ व्यक्तियों की मिशन मोड में जाँच करने का लक्ष्य रखा गया। कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत क्रियान्वित किया गया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े जनसंख्या-आधारित आनुवंशिक जाँच कार्यक्रमों में से एक बन गया है। इस मिशन का उद्देश्य 2047 तक SCD के आनुवंशिक संचरण को समाप्त करना और पहले से ही इससे पीड़ित लोगों को व्यापक देखभाल प्रदान करना भी है।

पहले दो वर्षों में, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से इस मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। 31 जुलाई 2025 तक, 17 उच्च-व्यापकता वाले राज्यों के 300 से अधिक जिलों में 6.07 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। जांच किए गए व्यक्तियों में से 2.16 लाख रोगग्रस्त पाए गए, जबकि 16.92 लाख को वाहक के रूप में पहचाना गया। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 95% मामले केवल पाँच राज्यों—ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र—में केंद्रित हैं।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के नवापारा की एक युवा आदिवासी लड़की मीना की कहानी इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव का प्रतीक है। जांच अभियान के दौरान नैदानिक परीक्षण किए जाने पर, मीना को निकट के एक उप-स्वास्थ्य केंद्र में नामांकित किया गया। प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम और आशा कार्यकर्ता ने यह सुनिश्चित किया कि उसे निःशुल्क हाइड्रोक्सीयूरिया औषधि समय पर मिलती रहे, जिससे सिकल सेल रोग के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी आई। आज, मीना पहले से कहीं अधिक स्वस्थ है और अपने समुदाय में आनुवंशिक रोगों के परामर्श में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। स्क्रीनिंग प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा अनुमोदित पॉइंट-ऑफ-केयर (PoC) डायग्नोस्टिक उपकरणों को लगाया गया है। शुरुआत में इनकी संख्या केवल तीन तक सीमित थी, जो अब बढ़कर 30 से अधिक हो गई है। इससे प्रति किट लागत ₹100 से घटकर ₹28 हो गई है। इस पहल ने SCD के लिए लागत-प्रभावी और कुशल डायग्नोस्टिक क्षमताएँ सुनिश्चित की हैं।

इस मिशन का कार्यान्वयन केवल स्क्रीनिंग पर केंद्रित नहीं है; यह एससीडी से पीड़ित व्यक्तियों की समग्र देखभाल को भी प्राथमिकता देता है। मिशन के अंतर्गत प्रबंधन हस्तक्षेपों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ, आवश्यक दवाओं और निदान तक पहुँच शामिल है। सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए एक प्रमुख दवा, हाइड्रॉक्सीयूरिया, को राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) में शामिल किया गया है और अब यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप-स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुँच सुनिश्चित होती है।

विकसित भारत के लिए मोदी का सुधारों का ब्रह्मास्त्र

जालंधर ब्रीज (नई दिल्ली) . मुझे अपने स्कूल के दिनों से ही 15 अगस्त के भाषणों में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है, लेकिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी का 12वें स्वतंत्रता दिवस का भाषण अभूतपूर्व और असाधारण था। इसमें विकसित भारत के पथ पर भारत की गति बढ़ाने के दिशा में सीधे तौर पर लक्षित-ब्रह्मास्त्र- अर्जुन का अकाट्य पौराणिक अस्त्र - छोड़ा गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्या प्तो असामान्ये उथल-पुथल के दौर के बीच, विकसित भारत का सपना संजोए भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में निरंतर आगे बढ़ना जारी रखे हुए है। यह भाषण केवल अपनी व्यापकता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने दायरे— साहसिक, भविष्योन्मुखी और 1.4 बिलियन लोगों के भाग्य को नया आकार देने में सक्षम अगली पीढ़ी के सुधारों —और उस विजन के प्रति स्पष्टता के लिए भी उल्लेखनीय है, जिसका यह राष्ट्रक इससे पहले कभी साक्षी नहीं रहा।

उदाहरण के लिए, डिजिटल इंडिया स्टैक को ही लें, यूपीआई दुनिया के आधे रीयल-टाइम लेनदेन के लिए उत्तरदायी है और साल के अंत तक होने वाला, पहली मेड-इन-इंडिया चिप का लॉन्चत, वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की अग्रणी स्थिति को दर्शाता है। ऐसे समय में जब राष्ट्रों की नियति सेमीकंडक्टर निर्धारित करते हैं, महत्वपूर्ण तकनीकों पर संप्रभुता का भारत का यह दावा किसी डिजिटल स्वराज से कम नहीं है।

ऊर्जा सुरक्षा लंबे समय से भारत के विकास की राह की सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है। दशकों तक, झिझक और "नो गो" क्षेत्रों ने अन्वेषण को बाधित किया और आयात पर निर्भरता बढ़ा दी। वह दौर अब बीत चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने ईईजेड में "नो गो" क्षेत्रों को लगभग 99% तक कम कर दिया है, जिससे 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ईएंडपी के लिए मुक्त हो गया है। ओएएलपी के साथ, इसने भारतीय और वैश्विक दिग्गजों, दोनों के लिए समान रूप से एक विशाल क्षेत्र खोल दिया है—हमारे हाइड्रोकार्बन बेसिन अब निष्क्रिय नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए उपयोग में लाए जाएँगे।

लाल किले की प्राचीर से घोषित ऐतिहासिक राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक महत्वाकांक्षी दूरदर्शी एजेंडा निर्धारित करता है। इस मिशन का लक्ष्य लगभग 40 वाइल्डकैट कुओं की ड्रिलिंग के माध्यम से 600-1200 मिलियन मीट्रिक टन तेल और गैस भंडारों का पता लगाना है। पहली बार, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक भारत अपनी जटिल अपतटीय सीमाओं को व्यवस्थित रूप से खोलेगा, एक ऐसे ढाँचे के साथ जो सूखे कुओं की स्थिति में 80 प्रतिशत तक और व्यावसायिक खोज पर 40 प्रतिशत तक लागत की वसूली की अनुमति देकर निवेश के जोखिम को कम करता है।

हरदीप एस पुरी
(लेखक केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं।)

यह पहल एक व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत 2032 तक घरेलू तेल और गैस उत्पादन को तिगुना बढ़ाकर 85 मिलियन टन और राष्ट्रीय भंडार को दोगुना करके एक से दो बिलियन टन के बीच किया जा सकता है। लगभग 8 मिलियन टन उत्पादन के बराबर, अतिरिक्त 100-250 बिलियन क्यूकबिक मीटर गैस उपलब्ध कराने के लिए प्लग-एंड-प्ले आधार पर अपतटीय साझा बुनियादी ढाँचा बनाया जाएगा। ये सभी उपाय न केवल पहले से अटकी हुई खोजों का मुद्रीकरण करेंगे, बल्कि एक आत्मनिर्भर ईएंडपी इकोसिस्ट म का निर्माण भी करेंगे, जहाँ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की हिस्सेदारी आज के 25-30 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। यह आज़ादी के बाद से भारत का सबसे व्यापक अपस्ट्रीम सुधार है।

साथ ही, ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तधर पर अग्रणी बनकर उभरा है। भारत 2030 के लक्ष्य से पाँच साल पहले ही 2025 तक 50% स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य तक पहुँच गया है। जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन प्रायोगिक स्तर से उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं; इथेनॉल मिश्रण और सीबीजी स्केल-अप एक नए ग्रामीण-औद्योगिक आधार का निर्माण कर रहे हैं; एलएनजी के बुनियादी ढाँचे का विस्तार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असैन्य परमाणु ऊर्जा को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान में, 10 नए परमाणु रिएक्टर चालू हैं, और भारत का लक्ष्य अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को दस गुना बढ़ाना है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भव्य योजना का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा हमारी औद्योगिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ऐसे समय में जब दुनिया लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व , निकल और कोबाल्ट के सामरिक महत्व को पहचान रही है, भारत ने 1,200 से अधिक स्थलों पर अन्वेषण शुरू किया है और साझेदारी, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण का ढाँचा तैयार कर रहा है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ईवी और उन्नत रक्षा क्षेत्र कभी भी बाहरी अवरोधों के अधीन न रहें।

राष्ट्रीय सुरक्षा लाल किला चार्टर का एक अन्य स्तंभ था। ऑपरेशन सिंदूर ने परमाणु ब्लैकमेल के युग का अंत करते हुए वास्तविक समय में भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और यह संदेश दिया कि आक्रमण का जवाब तेज़ी और कुशलता से दिया जाएगा। सिंधु जल संधि को स्थरगित करना संप्रभुता का साहसिक दावा है। सबसे बढ़कर, मिशन सुदर्शन चक्र का अनावरण, युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की रक्षा से प्रेरित है, जो मोदी की शैली— सभ्यतागत प्रतीकवाद के अत्याधुनिक तकनीक से मेल का प्रतीक है।

एक बहुस्तरीय स्वदेशी सुरक्षा कवच भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों की साइबर, भौतिक और हाइब्रिड खतरों से रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने हमारे लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करने वाले इंजनों के डिज़ाइन और निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय चुनौती जारी की है, और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और संस्थानों से संयोजन या असेंबली से ऑथरशिप तक की छलांग लगाने का आह्वान किया है।

प्रधानमंत्री ने कठोर सत्यों से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने उद्योग जगत और किसानों से आत्मनिर्भरता अपनाने और उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया। हालाँकि भारत दुनिया की फार्मेसी है, जो वैश्विक टीकों का 60% का उत्पादन करता है, अब इसे नई दवाओं, टीकों और उपकरणों के क्षेत्र में भी अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। यह बायोई3 नीति के तहत बायोफार्मा को निर्णायक बल देने के साथ-साथ है, जहाँ हमारी महत्वाकांक्षा ऐसी दवाओं का पेटेंट और उत्पादन करना है जो किफायती और विश्वस्तरीय दोनों हों।

घोषित किए गए कर और कानूनी सुधार भी उतने ही साहसिक हैं। महत्वऔपूर्ण बात यह है कि 1961 का आयकर अधिनियम, जो स्वयं उस युग का अवशेष है, अब बदला जा रहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला क्षेत्र में दो पुलिस अधिकारियों द्वारा एक पत्रकार पर कथित हमले का स्वत : संज्ञान लिया गया

जालंधर ब्रीज (चंडीगढ़) . राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के बटाला इलाके में दो पंजाब पुलिस अधिकारियों द्वारा एक पत्रकार पर सरेआम हमला करने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, घटना के एक वीडियो में, पीड़ित बेसुध पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पुलिसकर्मी उस पर हमला करने के बाद भाग रहे हैं।

- *राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई*
- *रिपोर्ट में जांच की स्थिति और पीड़ित के स्वास्थ्य की स्थिति शामिल होने की उम्मीद है*

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इसलिए, आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जाँच की स्थिति और पीड़ित पत्रकार के स्वास्थ्य की जानकारी शामिल होने की उम्मीद है। 7 अगस्त 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 1 अगस्त, 2025 को हुई थी। दोनों पुलिस अधिकारी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए बटाला में तैनात थे। पत्रकार ने कथित तौर पर उनकी उपस्थिति के बारे में कुछ सवाल पूछे जिससे वे भड़क गए और उन्होंने पत्रकार पर हमला कर दिया।

पंजाब सरकार के 24 घंटे बिजली के दावों को ठेंगा दिखा रहा एक्सियन फगवाड़ा

• **जालंधर ब्रीज .** विशेष रिपोर्टर

पंजाब के मुख्यमंत्री अक्सर अपने भाषणों में 24 घंटे और सस्ती बिजली मुहैया करवाने का दावा करते हैं परंतु जमीनी हकीक़त कुछ और ही है। इसकी जीती-जागती तस्वीर फगवाड़ा के दो गांव चेहरू-मेहरू है जिसमें दुनिया की स्थान रखने वाला प्रमुख यूनिवर्सिटी भी स्थित है। यूनिवर्सिटी के चांसलर को मौजूदा सरकार द्वारा ही राज्य सभा में भेजा गया। शायद उनको भी अपनी जिम्मेवारियों का एहसास नहीं है। जिन गांवों से यूनिवर्सिटी की पहचान दुनिया में बनी उसके लिए एक राज्यसभा मेंबर के नाते मूलभूत सुधार को दुरुस्त करने जैसे कि 24 घंटे बिजली, अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइट और क्राइम फ्री, गांव बनाकर इनको पूरे देश में मॉडल गांव की तरह दिखाते ताकि लोग यह ना कह सके कि इनको राज्यसभा क्यों भेजा और इसका जवाब लोगों को काम को देख कर खुद ही मिल जाता। कारोबारी के तौर पर वे अपने और परिवार के लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं वहीं जिस इलाके से उनको पहचान मिली उसका भी मूलभूत सुधार कर रहे हैं।

लेकिन हकीकत में इलाके के लिए उनका प्रयास कोसों दूर है। खुद की तरक्की के लिए तो दिन रात प्रयासरत हैं वहीं इलाके को राज्यसभा मेंबर के नाते नरक भोगने के लिए मजबूर लावारिस छोड़ा हुआ है। खुद की यूनिवर्सिटी की बिजली ना जाए उसके लिए पुख्ता प्रबंध है वहीं इलाके से इनका कोई सरोकार नहीं। इस इलाके की जिस अधिकारी को जिम्मेवारी दी गई उसको पता तक नहीं होता कि उसके निचले अधिकारी इलाके में क्या गुल खिला रहे हैं। लेकिन साहब तो मजे से एसी की ठंडी हवा में बैठकर अपनी सरकारी नौकरी के मजे ले रहे हैं। वहीं जनता भीषण गर्मी में बार-बार लंबे कट से परेशान हो रही है।

यहां तक की जनता को कट संबंधी कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही है ताकि समय रहते बिजली संबंधी जरूरी काम को निपटा सके। इस कार्य की जिम्मेवारी तैनात अफसरों की होती है कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के माध्यम से प्रेस नोट जारी करे।

हालात जो भी हो लेकिन यह तो तय है आने वाला समय ऐसे अफसर और अफसरशाही पंजाब सरकार को भारी पड़ने वाला है।

कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने 220 ग्राम हेरोइन बरामद की, 5 तस्कर गिरफ्तार

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

युद्ध नशे के विरुद्ध' को जारी रखते हुए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर 220 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने पिछले दो दिनों में विभिन्न थानों में नशा तस्करों और सप्लाई करने वालो के खिलाफ कार्रवाई की है और सदर थाने में 20 ग्राम हेरोइन के साथ एक व्यक्ति और कैंट थाने में 200 ग्राम हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दो मामले दर्ज कर कुल 220 ग्राम हेरोइन बरामद की है।

इसके अलावा, थाना डिवीजन नंबर 1, 3 और बस्ती बावा खेल में 3 अन्य पुराने मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियान नशे के हॉटस्पॉट और तस्करी के ठिकानों पर लक्षित है। इन अभियानों के दौरान कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ नशा पीड़ितों के पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत कुल 10 व्यक्तियों को इलाज और पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाया गया है। पुलिस कमिश्नर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जालंधर कमिश्नरेट पुलिस समाज से नशे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वचनबद्ध है।

दिल्ली मे हारी आप पंजाब मे भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई : सुशील शर्मा

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

भाजपा जिला जालंधर के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने वीरवार को जालंधर के पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू एवं पूर्व संसदीय सचिव पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण देव भंडारी पर पंजाब पुलिस के पक्षपात रवैया अपनाया है और सरकार के दबाव में जो गिरफ्तारी की है वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद आम आदमी पार्टी बौखला गई है और अब पंजाब में पुलिस का इस्तेमाल कर भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने की कोशिश कर रही है।

सुशील शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है और अब वह पुलिस का इस्तेमाल कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है। भाजपा जिला महामंत्री अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि ना झुकेंगे ना रखेंगे और ना थकेंगे जनता को मोदी सरकार से मिलने वाले लाभ दिलाके रहेंगे भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की इन कोशिशों से नहीं डरेंगे और जनता को मोदी सरकार के लाभ पहुंचाने के लिए काम करते रहेंगे व जनता के हितों के लिए लड़ते रहेंगे और मोदी सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएंगे।

दोनों नेताओं ने पंजाब के लोगों से आग्रह किया कि वे आम आदमी पार्टी की इन कोशिशों को समझें और भाजपा के साथ देवही दोनों नेताओं ने कहा जालंधर शहरी इलाके मे भी जल्द योजना बनाकर जरूरतमंद लोगो को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना,आयुष्मान योजना,जनधन योजना,स्टार्ट अप,मुद्रा योजना जैसी दर्जनों योजनाओं का सीधा लाभ

• भाजपा नेताओ की गिरफ्तारी के बाद धरना प्रदर्शन करते सुशील शर्मा, अशोक सरीन हिक्की, जॉर्ज सागर व अन्य।

कैम्प मे कार्ड बनाकर देगें। इस अवसर पर पार्षद मनजीत टीटू, कंवर सरताज, मंडल प्रधान जॉर्ज सागर, कुलदीप मानक, राजेश मल्होत्रा, कुलवंत शर्मा,अनिल सच्चर, रविंद्र धीर, अनुज शारदा, गौरव राय,भगवंत परभाकर, राजीव ढींगरा, अश्वनी भंडारी, अमरजीत अमरी, अजमेर बादल आदि भारी संख्या मे भाजपा कार्यकर्ता धरणों में शामिल हुए।

भारतीय वायु सेना भर्ती रैली 30 अगस्त और 2 सितंबर को

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

जिला रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण ब्यूरो की उप निदेशक नीलम महे ने बताया कि भारतीय वायु सेना, जिला प्रशासन के सहयोग से सरकारी आर्ट्स एवं स्पोर्ट्स कॉलेज में एक खुली भर्ती रैली का आयोजन कर रही है। उप निदेशक ने आगे बताया कि पंजाब राज्य के लड़कों के लिए भर्ती रैली 30 अगस्त 2025 को और पंजाब राज्य की लड़कियों के लिए 2 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए प्रवेश समय सुबह 5 बजे होगा।

उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार का जन्म 01.01.2005 और 01.07.2008 के बीच हुआ हो और उसकी शैक्षणिक योग्यता 10+2, डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्स पास (कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक और अंग्रेजी विषय में 50% अंक) होनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि मैडिकल योग्यता के अंतर्गत, उम्मीदवार लड़के और लड़कियों की ऊँचाई 152 सेमी होनी चाहिए।

उप-निदेशक ने आगे बताया कि अधिक जानकारी भारतीय वायु सेना की वेबसाइट https://agnipathvayu.cdac.in से प्राप्त की जा सकती है या जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो जालंधर के हेल्पलाइन नंबर 90569-20100 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने युवा लड़के-लड़कियों से अपील की कि वे इस भर्ती रैली में अधिक से अधिक भाग लें।

10 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम हटाना ग़रीबों पर सीधा अत्याचार

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने केंद्र की भाजपा सरकार के नये फ़ैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पंजाब के लाखों ग़रीब परिवारों से रोटी छीनने की साज़िश रची जा रही है। भाजपा सरकार ने 10 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाकर यह साबित कर दिया है कि उसकी नीतियाँ ग़रीबों के हितों की जगह केवल राजनीतिक बदले पर आधारित हैं।

मोहिंदर भगत ने कहा कि यह फ़ैसला न सिर्फ़ ग़रीबों के लिए घातक है, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के भी खिलाफ़ है। जिन परिवारों का गुज़ारा सरकारी राशन पर निर्भर है, उन्हें भूखा मरने पर मजबूर करना किसी भी सुशासन का हिस्सा नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि पंजाबी किसानों ने हमेशा देश की भूख मिटाने के लिए बलिदान दिए हैं, लेकिन आज केंद्र सरकार उन्हीं परिवारों के मुँह का निवाला छीनने पर तुली हुई है।

मोहिंदर भगत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हमेशा पंजाब के साथ भेदभाव की नीति अपनाती आई है। कभी किसानों से, कभी उद्योगों से और अब ग़रीबों से। यह नीति केवल पंजाबियों को उनके अधिकारों से वंचित करने की मानसिकता को दर्शाती है।

पंजाब औद्योगिक बुनियादी ढांचे के रख-रखाव के लिए स्वतंत्र अथॉरिटी स्थापित करेगा

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने 'राइजिंग पंजाब - सुझावों से समाधान तक' कार्यक्रम में पहलकदमियों को उजागर किया

• **जालंधर ब्रीज.** लुधियाना

पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार पंजाब भर के सभी फोकल प्वाइंटों और औद्योगिक एस्टेट्स में बुनियादी ढांचे के रख-रखाव की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र अथॉरिटी स्थापित करने की योजना बना रही है। इस अथॉरिटी का उद्देश्य सीवरेज, सड़कों, रोशनी और औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करना है। गुरुवार को लुधियाना में आयोजित 'राइजिंग पंजाब - सुझावों से समाधान तक' कार्यक्रम में बोलते हुए अरोड़ा ने खुलासा किया कि वैश्विक सलाहकार फर्म अर्नस्ट एंड यंग इस अथॉरिटी के लिए एक ढांचा तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही लागू करने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में लुधियाना, मोगा, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब के उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने सरकारी नीतियों को आकार देने के लिए मूल्यवान सुझाव दिए।

अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि पिछले साढ़े तीन सालों के दौरान कारोबार को आसान बनाने पर पंजाब ने 1.14 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 4.5 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा हुआ है। मंत्री ने घोषणा की कि 13 मार्च 2026 से आई.एस.बी. मोहाली में तीन दिवसीय पंजाब निवेश सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के दिए निर्देश

• **जालंधर ब्रीज.** फगवाड़ा

पंजाब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन चंदन ग्रेवाल ने फगवाड़ा में जिला अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। गुरुवार को यहां नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान ग्रेवाल ने कहा कि पंजाब को स्वच्छ बनाने वाले सफाई कर्मचारियों को हर संभव सुविधा प्रदान की जाए।

सफाई कर्मचारियों को वर्दी, समय पर वेतन, स्वास्थ्य सुविधाएं और काम के लिए उपकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ जिन कर्मचारियों को अपने बैंक खातों से संबंधित के.वाई.सी. आदि की समस्या है, उसे भी हल करवाया जाएगा। ठेकेदारों द्वारा नियमों का पालन न करने के बारे में सख्त कार्रवाई के आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी अनियमितता को वह व्यक्तिगत रूप से देखेंगे और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

चंदन ग्रेवाल ने कहा कि पंजाब को स्वच्छ बनाने वाले सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों को वर्दी, समय पर वेतन, स्वास्थ्य सुविधाएं और काम के लिए उपकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ जिन कर्मचारियों को अपने बैंक खातों से संबंधित के.वाई.सी. आदि की समस्या है, उसे भी हल करवाया जाएगा। चेयरमैन ने ठेका आधारित सफाई कर्मचारियों से उनके वेतन और मजदूरी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बैंक खातों में पैसे आने के संबंध में मोबाइल फोन पर मैसेज की सुविधा लागू करवाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश जारी किए।

एसपीसीए की बैठक में 75 लाख की लागत से होने वाले कार्यों को प्रशासकीय मंजूरी

गौशाला की क्षमता बढ़ने से अधिक संख्या में पशुओं का उचित रख-रखाव सुनिश्चित होगा : डिप्टी कमिश्नर

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

बेसहारा पशुओं के उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित ज़िला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी (एसपीसीए) की बैठक में कनिया कलां गौशाला में लगभग 75 लाख रुपये की लागत से एक नए शेड के निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) जसबीर सिंह के साथ जिला प्रशासकीय परिसर में बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस परियोजना के तहत कनिया कलां गौशाला में नए शेड के निर्माण के अलावा, अन्य कार्यों में जलापूर्ति और रोशनी का प्रावधान, मौजूदा शेड का फर्श और रंग-रोगन, पशु तालाब की सर्विस लेन और अन्य कार्य शामिल है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के पूरा होने से गौशाला की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बड़ी संख्या में पशुधन की उचित संभाल सुनिश्चित होगी। उन्होंने संबंधित कार्यकारी एजेंसी को अक्तूबर के अंत तक इस परियोजना को पूरा करने का भी निर्देश दिया। नगर निगम जालंधर और नगर परिषदों को गौ उपकर एकत्र करने पर जोर देते हुए, डा. अग्रवाल ने कहा कि उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र से गौ उपकर एकत्र किया जाना चाहिए और समय पर जमा किया जाना चाहिए ताकि इसे गौवंश के कल्याण के लिए खर्च किया जा सके।

नवनियुक्त 54 पटवारियों का स्वागत

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर में 54 नवनियुक्त पटवारियों का स्वागत किया और उन्हें पूरी लगन, मेहनत और जिम्मेदारी से जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। नवनियुक्त पटवारियों को बधाई देते हुए डा.अग्रवाल ने कहा कि वह बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें जमीनी स्तर पर जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। पटवारियों को राजस्व विभाग की रीढ़ बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास गिरदावरी, जमीन की निशानदेही, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की संभाल और जमीनी स्तर पर की जाने वाली प्रक्रियाओं के उचित क्रियान्वयन सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां है। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पटवारी फील्ड में पंजाब सरकार के प्रतिनिधि है। डा. अग्रवाल ने कहा कि उनके द्वारा दी गई सटीक रिपोर्ट किसानों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ राजस्व विभाग के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होती है। डा.अग्रवाल ने राजस्व विभाग में पटवारियों की भर्ती के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदमों की प्रशंसा की।

'भाजपा दे सेवादार आगए ने तुहाड़े द्वार' अभियान से डर गई है सरकार : सांपला

जालंधर (जालंधर ब्रीज). आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पंजाब में 39 स्थानों पर "भाजपा दे सेवादार आगए ने तुहाड़े द्वार" अभियान को पुलिस के बल से रोकने की, जनविरोधी और तानाशाही कार्रवाई की भाजपा कड़ी निंदा की है। भाजपा पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस अभियान को जबरदस्ती रोक दिया, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही थी। विजय सांपला ने आरोप लगाया कि विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करने और जरूरतमंदों को पंजीकृत करने में सहायता करने का अभियान उस समय पूरी तरह से ठप हो गया जब भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने जानबूझकर हस्तक्षेप किया। गरीबों, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और युवाओं को सशक्त बनाने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं का समर्थन करने के बजाय, पंजाब सरकार ने पुलिस बल का दुरुपयोग कर इन्हें रोकने का काम किया है।

द्विपक्षीय मुकाबले नहीं होगे पर भारतीय टीम को एशिया कप खेलने से नहीं रोकेंगे : खेल मंत्रालय

स्पोर्ट्स डेस्क. टी20 एशिया कप 2025 के शेड्यूल के ऐलान होते ही बीसीसीआई की चारों तरफ आलोचना होने लगी थी जिसके बाद कहा जाना लगा कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को होने वाले मैच से पीछे हट जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। भारतीय चाहते हैं कि जब भारत से पाकिस्तान परस्त आतंकवाद खत्म न हो तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई खेल या कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। इस बीच खेल मंत्रालय का बयान सामने आया है। खेल मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय खेल मुकाबले नहीं होंगे लेकिन

भारतीय टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोका जाएगा।

दरअसल, गुरुवार को खेल मंत्रालय ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय खेल संबंधों के संबंध में नई नीति जारी की है, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान के साथ संबंधों पर जोर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार ये नीति तुरंत प्रभावी हो गई है। खेल मंत्रालय की नीति में कहा गया है कि पाकिस्तान से जुड़े खेल आयोजनों में भारत का दृष्टिकोण उसी व्यापक नीति को दर्शाता है जो उस देश के साथ भारत के संबंधों में अपनाई गई है। जहां तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय खेल आयोजनों का सवाल है तो भारतीय टीम पाकिस्तान में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेगी। पाकिस्तान की टीमें भी भारत में द्विपक्षीय मैच खेलने की अनुमति नहीं पाएंगी। वहीं, मंत्रालय के एक स्त्रोत ने कहा कि हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे क्योंकि ये एक बहुदेशीय प्रतियोगिता है।

होशियारपुर से होगी 'खेडां वतन पंजाब दीयां' की शुरुआत

प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम 3 सितंबर को लाजवंती मल्टीपरपज स्टेडियम में होगा आयोजित

• **जालंधर ब्रीज.** होशियारपुर

पंजाब सरकार की ओर से खेलों व युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान "खेडां वतन पंजाब दीयां" की शुरुआत इस बार होशियारपुर से होगी। इस संबंधी प्रदेश स्तरीय उद्घाटन समारोह 3 सितंबर को लाजवंती मल्टीपरपज स्टेडियम, होशियारपुर में बड़े उत्साह और जोश के साथ आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश स्तरीय खेल मुकाबलों की भी शुरुआत होगी।

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने आज जिला प्रशासनिक परिसर में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समागम की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन को सफल और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की कमी न रहने देने के निर्देश दिए।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की यह पहल केवल खेल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने और उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का भी एक सशक्त माध्यम है।

बैठक के दौरान विभिन्न कार्यों को सुचारु रूप से सम्पन्न करने हेतु अलग-अलग कमेटियों का गठन किया गया। हर कमेटी को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें खेल मुकाबलों की व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन, अतिथियों का स्वागत, सुरक्षा प्रबंध, यातायात नियंत्रण, चिकित्सा सुविधा, पेयजल और साफ-सफाई संबंधी इंतज़ाम शामिल हैं।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, Near Subhanpur Bus Stand,Hamira, Kapurthala-144802(Punjab) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.